भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 109
सोमवार 1 दिसंबर, 2025
10 अग्रहायण, 1947 (शक)

109. श्री राहुल गांधीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 2026 तक आईडीबीआई बैंक का निजीकरण पूरा करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो इसके निजीकरण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विनिवेश प्रक्रिया के तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने वाले या वित्तीय बोलियों के लिए योग्य पाए गए बोलीदाताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने का क्या औचित्य है;

(घ) पिछले दस वर्षों में आईडीबीआई बैंक के परिचालन लाभ का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और आईडीबीआई बैंक की मूर्त और अमूर्त संपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को आगे बढ़ाने के बजाय किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक के साथ उसके विलय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या वह इस पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने वर्तमान कर्मचारियों, जमाकर्ताओं तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर निजीकरण के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 05.05.2021 को हुई अपनी बैठक में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो कि भारत सरकार और एलआईसी में शेयरधारिता की उस सीमा तक होगा, जो एलआईसी के साथ परामर्श करके और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नियत फ्रेमवर्क के भीतर तय किया जाएगा।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश करने के लिए मई 2021 में सीसीईए (आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति) के अनुमोदन के अनुसरण में, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश करने के लिए 60.72% आईडीबीआई बैंक इक्विटी की पेशकश की जा रही है, जिसमें भारत सरकार 30.48% की पेशकश कर रही है (बिक्री के पश्चात भारत सरकार की अधिशेष इक्विटी 15% हो जाएगी) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) विनिवेश के लिए 30.24% इक्विटी की पेशकश कर रही है (बिक्री के पश्चात एलआईसी की अधिशेष इक्विटी 19% हो जाएगी)।

संभावित बोलीदाताओं से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए दिनांक 7 अक्तूबर, 2022 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) प्रकाशित किया गया था। पीआईएम पर प्रतिक्रिया के रूप में विभिन्न रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त हुईं थी। इन ईओआई को सुरक्षा अनापत्ति के लिए गृह कार्य मंत्रालय (एमएचए) को और 'सही और उचित' मूल्यांकन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को भेजा गया था। गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनापत्ति और आरबीआई से 'सही और उचित' मूल्यांकन की मंजूरी मिलने के बाद, यह सौदा अभी चुने गए बोलीदाताओं (एसबी) द्वारा उचित अध्यावसाय के चरण में है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, सौदा पूरा होने से पहले बोलीदाताओं की पहचान नहीं बताई जा सकती।

(ग) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पिछले 10 वर्षों के परिचालन लाभ का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	**मार्च-25**	**मार्च-24**	**मार्च-23**	**मार्च-22**	**मार्च-21**	**मार्च-20**	**मार्च-19**	**मार्च-18**	**मार्च-17**	**मार्च-16**
परिचालन लाभ	11079	9592	8736	7495	7091	5112	4052	7905	4578	5370

स्रोत: आईडीबीआई बैंक

मार्च 2025 में, आईडीबीआई बैंक के पास लगभग 4.11 लाख करोड़ रुपए की बकाया पूंजी और देनदारियाँ थीं, जो उतनी ही राशि की कुल परिसंपत्तियों (मूर्त और अमूर्त) द्वारा समर्थित थीं।

(ङ) जी नहीं, आईडीबीआई बैंक का विनिवेश सीसीईए अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा।

(च) से (छ) चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) (11 कंपनियों) के प्रदर्शन पर रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण के प्रभाव का विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) के अध्याय 9 में किया गया था। इससे पता चलता है कि निजीकृत सीपीएसई ने निजीकरण के बाद निवल मूल्य, शुद्ध लाभ, इक्विटी पर रिटर्न, परिसंपत्तियों पर रिटर्न, सकल राजस्व, शुद्ध लाभ मार्जिन, बिक्री वृद्धि और प्रति कर्मचारी सकल लाभ के मामले में अपने समकक्षों की तुलना में औसतन बेहतर प्रदर्शन किया।

****